महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2015-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

स्वतंत्रता दिवस पर समस्त देशवासियों को सृष्टि एग्रो परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

सृष्टि एग्रो

वर्ष-6 | अंक-14 | मुंबई, 16 से 31 अगस्त 2018 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

महाराष्ट्र में तिलहन फसलों की बुआई ने तोड़ा पांच सालों का रिकार्ड

सुरेंश शर्मा

मुंबई। चालू खरीफ सीजन में फसलों की कुल बुआई भले ही पिछड़ी नजर आ रही है लेकिन सोयाबीन की बुआई पिछले साल की अपेक्षा करीब 11 फीसदी अधिक हुई है। महाराष्ट्र में तो तिलहन फसलों की बुआई ने पिछले पांच वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा बुआई सोयाबीन की हुई है। राज्य में सोयाबीन की बुआई सरकारी अनुमान और सोयाबीन के कुल रकबे को भी पार कर गई है। खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। मॉनसून की अटपटी चाल की वजह से इस बार खरीफ फसलों की बुआई देश में पिछले साल की अपेक्षा कुछ कम हुई। लेकिन तिलहन फसलों की बुआई शानदार दिख रही है। प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में बुआई ने पिछले पांच सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तिलहन फसलों में सोयाबीन की बुआई सबसे ज्यादा हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और महाराष्ट्र कृषि मंत्रालय के बुआई के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 3 अगस्त तक 37.488 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई जबकि पिछले साल यानी 2017 में इस समय तक राज्य में 35.449 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। महाराष्ट्र में 2016 में 36.806 लाख हेक्टेयर,

2015 में 32.198 लाख हेक्टेयर और 2014 में 25.798 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। राज्य में 3 अगस्त तक का सोयाबीन का औसत रकबा 33.652 लाख हेक्टेयर है जबकि खरीफ सीजन का कुल सामान्य रकबा 35.84 लाख हेक्टेयर है। महाराष्ट्र कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोयाबीन का बुआई अनुमान से भी बेहतर हुई है। किसानों को सोयाबीन में फायदा दिख रहा है, सरकार भी किसानों को उन फसलों की तरफ प्रोत्साहित करती है जिनमें किसानों को ज्यादा फायदा हो। सोयाबीन का रकबा बढ़ने की प्रमुख वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाकर 3,399 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है जो पिछले खरीफ सीजन में 3,050 रुपये प्रति क्विंटल था। सोयाबीन का रकबा बढ़ने की वजह से तिलहन फसलों का रकबा पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा दिख रहा है। देश में तिलहन फसलों का रकबा करीब 11 फीसदी अधिक हुआ, जबकि महाराष्ट्र में तिलहन फसलों का रकबा पिछले साल की अपेक्षा करीब छह फीसदी अधिक है। इसके बावजूद राज्य में तिलहन फसलों का रकबा पांच साल में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 3 अगस्त तक तिलहन फसलों की बुआई का रकबा 39.498 लाख हेक्टेयर हो चुका है। पिछले साल इस समय तक महाराष्ट्र में तिलहन फसलों की बुआई 37.744 लाख हेक्टेयर में हुई थी जबकि राज्य में खरीफ सीजन के दौरान तिलहन फसलों का कुल रकबा 39.20 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है। देशभर के किसानों ने इस बार सोयाबीन की जमकर बुआई की है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 अगस्त तक देश में सोयाबीन का रकबा पिछले साल की अपेक्षा 11 फीसदी बढ़कर 109.50 लाख हेक्टेयर पहुंच गया।

12 कीटनाशकों पर रोक, 6 पर दिसंबर 2020 तक लगेगी रोक

नई दिल्ली (विसं)। आखिरकार केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक 18 कीटनाशकों पर रोक लगाने का फैसला किया है, इनमें से 12 कीटनाशकों पर जहां तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं 6 कीटनाशकों को क्रमवार वर्ष 2020 तक प्रतिबंधित किया जायेगा। केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति ने अपनी सिफारिश में इन कीटनाशकों से होने वाले संभावित नुकसान पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद केंद्र ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन कीटनाशकों के इस्तेमाल पर कई देशों ने पहले से ही पाबंदी लगा रखी है। सरकार ने बेनोमिल, फेनारिमोल, कार्बोसल्फ, मिथाँक्सी एथाइल मरकरी क्लोराइड, थियोमेटॉन समेत जिन 12 कीटनाशकों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया गया है जबकि एलाक्लोर, डिक्लोरवास, फोरेट और फोस्फामिडॉन आदि को देश में 2020 तक प्रतिबंधित करना होगा। इन कीटनाशक से मनुष्यों के साथ ही पशु-पक्षियों पर इसके घातक परिणाम दिख रहे थे। हालांकि इसमें वो कीटनाशक ग्लायफोसेट शामिल नहीं है, जिसके लिए अमेरिका में मॉनसेंटो को एक कैंसर मरीज को भारी हर्जाना देने को कहा गया है। कीटनाशकों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने 16 जुलाई को इस मुद्दे पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसने सिफारिशों में कहा कि ये कीटनाशक लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। विभिन्न स्तरों पर इनका प्रयोग फसल को बिषैला बनाता हैं। इसी वजह से कई देशों ने इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखा है। समिति ने कहा कि इन्हें प्रतिबंधित किया जाना ही उचित व्यवस्था होगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन कीटनाशकों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है, उनका निर्माण करने वाली कंपनियों को देशभर में मौजूद इन कीटनाशकों का इस्तेमाल रोकने के लिए चेतावनी जारी करनी होगी।

जैविक खेती को पहली बार बढ़ावा पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ही दिया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही ने बताया कि किसानों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी काफी संवेदनशील थे। वाजपेयी के कार्यकाल में वह और हुक्मदेव नारायण सिंह किसान क्रेडिट कार्ड के आइडिया को लेकर वाजपेयी के पास गए। तब हुक्मदेव नारायण किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। सिरोही के मुताबिक, उन लोगों ने वाजपेयी को बताया कि किसानों के पास नकदी की कमी होती है। इस कारण उनके पास खरीदारी के विकल्प कम होते हैं और उन्हें गांव के दुकानदारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में, किसानों की जमीन की हैसियत के मुताबिक अगर उन्हें क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए तो किसान शहर में जाकर अपने मुताबिक खरीदारी

कर पाएंगे। सिरोही ने बताया कि वाजपेयी ने इस आइडिया को सुनते ही ओके कर दिया। सिरोही ने बताया कि किसानों को लेकर टेलीविजन चैनल की शुरुआत भी वाजपेयी की देन है। उन्होंने याद करते हुए बताया कि कैसे किसान मोर्चा की तरफ से किसान चैनल आरंभ करने का पूरा प्रस्ताव वाजपेयी को दिया गया था और उन्होंने 7 रेस कोर्स रोड से ही किसान चैनल की शुरुआत की थी। जैविक खेती के लिए अलग से नीति पहली बार वाजपेयी सरकार के जमाने में बनाई गई। शास्त्री जी ने जैविक खेती के लिए अलग से नीति का विरोध किया। सिरोही ने बताया कि फिर अजीत सिंह के कहने पर किसान मोर्चा के लोगों ने जैविक खेती की नीति के लिए सुदर्शन से कहा और उन्होंने वाजपेयी से। फिर जैविक खेती के लिए नीति बनी।

497 बीज विकसित, खराब मौसम में फसल नहीं होगी खराब

कृषि मंत्रालय ने 720 में से 623 जिलों की जलवायु के अनुसार अलग-अलग प्लान तैयार किया है इन जिलों के लिए 497 ऐसे बीज तैयार किए हैं, जो विषम परिस्थितियों में पूरी पैदावार देंगे

नई दिल्ली (विसं)। किसानों की सबसे बड़ी परेशानी फसलों पर खराब मौसम की मार है। लेकिन अब देश में ऐसी खेती होगी, जिस पर मौसम का असर नहीं पड़ेगा। पैदावार भी अधिक होगी। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने 720 में से 623 जिलों की जलवायु के अनुसार अलग-अलग प्लान तैयार किया है। इन जिलों के लिए 497 ऐसे बीज तैयार किए हैं, जो विषम परिस्थितियों में पूरी पैदावार देंगे। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद ने इस तरह की खेती कराने की शुरुआत भी कर दी है। धान की 13 प्रजाति के ऐसे बीज तैयार किए गए हैं जो 20-20 दिन तक पानी में डूबे रहने के बाद भी नष्ट नहीं होंगे। इसी तरह सूखे पर भी सामान्य पैदावार करने वाले 15 बीज ईजाद किए गए हैं। इसके अलावा गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, अलसी, चना, मसूर, ग्वारफली, गन्ना समेत कई फसलों के बीज तैयार किए गए हैं, जिन्हें बाढ़, सूखे के अलावा बीमारी होने या कीटाणु की चपेट में आने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. शामी रेड्डी ने बताया कि सभी 623 जिलों में इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। इस वर्ष के अंत तक सभी जिलों के लिए योजना तैयार हो जाएगी। किसान विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्लान के अनुसार खेती करने का काम शुरू हो चुका है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद के तहत काम करने वाले 'नेशनल इनीशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेसीलिएंट एग्रीकल्चर' विभाग ने पूरा प्लान तैयार कराया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने 497 बीज विकसित किए हैं। इन बीजों से पैदा होने वाली फसल पर सूखे, बाढ़, बीमारी और कीटाणु लगने जैसी विषम परिस्थितियों को असर नहीं पड़ेगा।

किसानों को बचाने के लिए तैयार हुआ प्लान

नेशनल इनीशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेसीलिएंट एग्रीकल्चर ने देशभर के 700 कृषि विज्ञान केन्द्रों को मदद से प्रत्येक जिले की जलवायु का अध्ययन किया। इसमें खेत की मिट्टी, मौसम, भूमि उपयोग, जलवायु, नमी, मिट्टी का स्लोप आदि शामिल किया गया। इसके अलावा जिले में बाढ़ और सूखे के आंकड़े इकट्ठे कर हर जिले की रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद वैज्ञानिकों ने दोनों अध्ययनों के अनुसार जिलों की जलवायु के आधार पर प्लान तैयार किया, जिसमें किसानों को सुझाव दिया कि किस जिले के लिए कौन सी फसल और उसकी प्रजाति अच्छी रहेगी और कौन सी फसल नुकसान देने वाली रहेगी। बोने से सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा और क्या-क्या सावधानी बरतने की जरूरत है।

सम्पादकीय

जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम

जलवायु परिवर्तन की थमक तेज होती जा रही है। इस वर्ष जून और जुलाई महीनों में अकेले कैलिफोर्निया के वनों में 140 बार आग लगी। ग्रीस में जंगलों में लगी आग से 80 लोग मारे गए। यूरोप गरम हवाओं से तपता रहा, भारत में बिना मौसम के आए धूल के तूफानों ने 500 से अधिक लोगों की जान ले ली। जापान तथा अन्य जगहों पर बेतहाशा बारिश होने से फसल नष्ट हो रही हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। ये सारी घटनाएं असामान्य हैं। अतीत में इन घटनाओं की स्थिरता के बजाय अब हम ऐसे युग में हैं जहां सबकुछ अनजाना और अप्रत्याशित है। हमें यह अवश्य पता है कि आने वाले दिनों में अजीबोगरीब मौसम की यह तीव्रता और अधिक बढ़ने वाली है। मौसम में इस अतिरींजत बदलाव और जलवायु परिवर्तन के आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया जा रहा है। विश्व मौसम संबंध नेटवर्क का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप में गरम हवा के थपेड़ों की तादाद दोगुनी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में सूखे की आशंका में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल ही में इस शहर में पानी खत्म होते-होते बचा है। प्रश्न यह है कि अब आगे क्या? आने वाले महीने में जब वैश्विक तापवृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी तब जलवायु परिवर्तन का अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट वही बातें बताएगी जो हम सब पहले से जानते हैं। अगर मौसम से जुड़ी ऐसी विपत्तियां 1 डिग्री सेल्सियस पर महसूस की जा सकती हैं जो कि औद्योगिक युग के पूर्व का स्तर है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर तो परिस्थितियां और खराब होती जाएंगी। अब हमें क्या करना होगा? एक बात एकदम स्पष्ट है कि हालात बद से बदतर होते जाएंगे। सच तो यह है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं रह सकते। एक वक्त था जब इस तापवृद्धि को काफी हद तक सुरक्षित माना गया था।

हम बहुत तेजी से उत्सर्जन और तापमान के सभी अवरोध तोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन मुद्दा यह है कि अब जबकि अमीरों पर भी जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है और ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का संबंध स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके बावजूद गुस्से का निशाना भारत जैसे उभरते देशों के नए अमीर होते हुए लोगों को बनाया जाएगा। आज वातावरण में जो भी उत्सर्जन मौजूद है, हम उसके पीड़ित नहीं उसकी वजह हैं। सच तो यह है कि भारत और चीन कोयला जलाने से होने वाले उत्सर्जन के नुकसान से परिचित हैं क्योंकि दोनों देश वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में हमें पुराने पड़ चुके और प्रदूषण फैलाने वाले ताप बिजली घरों को बंद करने की आवश्यकता है। दिल्ली के बदरपुर में स्थित संयंत्र को इन जाड़ों में बंद कर दिया जाएगा। नए उत्सर्जन मानकों का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाएगा। पेट कोक पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। मेरिका से इसके आयात पर भी रोक लग चुकी है। अब हमें नवीकरणीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की दिशा में बढ़ना होगा। यह जरूरी है और हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसा करना जलवायु परिवर्तन की वजह से आवश्यक नहीं है बल्कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए भी यह जरूरी है। परंतु तथ्य यह है कि दुनिया का कार्बन बजट समाप्त हो चुका है। पहले से अमीर देशों ने अपनी वृद्धि के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब कुछ भी शेष नहीं है तो हमसे त्याग करने को कहा जा रहा है। प्रत्युत्तर भी तैयार है। पहले हमसे अपराधबोध और पश्चाताप की भाषा बचाव का तरीका है क्योंकि यह कहीं नहीं ले जाती। उसके बाद हमसे कहा जाएगा कि अगर समस्या अमीरों द्वारा बनाई गई है तो भी हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। हम पर जिम्मेदारी है। यह सवाल हमारे बच्चों और जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों का है। यह दुनिया के गरीबों और वंचितों का है। समस्या यह भी है कि दुनिया अभी जीवाश्म ईंधन से अपना लगाव कम नहीं कर पा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो जर्मनी के अलावा अभी भी आपूर्ति बहुत कम है। दरअसल बीते वर्ष कोयले की मांग में इजाफा देखने को मिला। तेल और गैस में निवेश बढ़ा और जलवायु परिवर्तन संबंधी तमाम प्रयास अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कारगर नहीं साबित हुआ। परंतु हमारी सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। सच तो यह है कि भारत जैसे देशों को आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन की आर्थिक और मनुष्यगत लागत पर बात करनी चाहिए। यह वैश्विक मंच पर एक त्रासदी की तरह घटित हो रही है। हमें यह मांग करनी चाहिए कि दुनिया इस दिशा में तेजी से कार्रवाई करे। जब हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सह-लाभ के लिए अपनी योजनाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए।

बेबी कॉर्न मक्के की उन्नत खेती

बेबी कॉर्न मक्के के भुट्टे की प्रारम्भिक अवस्था है जिसमें भुट्टे के परागन से पहले की कोमल अवस्था में तोड़ लिया जाता है. जिसे बेबी कॉर्न कहते है इसमें 2 से 3 सेन्टीमीटर तक सिल्क (बालयामोचा) निकले रहते है, इसकी तुड़ाई सिल्क निकलने के 1 से 2 दिन के अन्दर कर लेना चाहिए. इसकी तुड़ाई मौसम पर आधरित है। आज कल बेबी कॉर्न की खेती लोकप्रिय हो रही है जिसका उपयोग सब्जी या सलाद के रूप में बहुत किया जा रहा है। इसका उपयोग थाईलैंड ताईवान हांगकांग आदि देशों में काफी पहले से किया जा रहा है, परन्तु अब अरब देशों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है इसको सब्जी एवं सलाद के साथ-साथ आचार पकौड़ा तथा अन्य कई चाइनीस पकवान भी तैयार किये जाते हैं। बेबी कॉर्न बहुत पौष्टिक होता है जसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन फोस्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ-साथ हरे पौधों से पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त होता है इससे साइलेज भी तैयार की जा सकती है। साइलेज में 13.5प्रश. प्रोटीन 1.4प्रश. वसा 34.8प्रश. रेशा 6.5 प्रश. रेश पाया जाता है जो पशुओं के लिए संतुलित आहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बेबी कॉर्न की मांग बढ़ने का एक मुख्य कारण यह है की इसमें रसायनों आदि से बिल्कुल कम या प्रभावित नहीं होती है क्योंकि भुट्टा ऊपर से कई पत्तों के हस्क से ढका रहता है।

भारत में बेबी कॉर्न की खेती शुरू से महानगरों के आस-पास तक सीमित है क्योंकी इन महानगरों में विभिन्न बड़े होटल हैं जहां इसकी मांग अधिक है लेकिन अब इसकी खेती का प्रचलन उत्तर-प्रदेश के आगरा मथुरा, अलीगढ़ महाराष्ट्र के पुणे एवं नासिक बिहार के पूर्णिया ,बांका, कटिहार एवं बेगुसराय आदि जिलो में भी किया जा रहा है।

बीजोपचार: सर्वप्रथम बीज थीरम या कैप्टान आदि रसायनों से 25 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित कर लेना चाहिए.

पादप सघनता: बेबी कॉर्न की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 110000 से 115000 पौधे प्रति हैक्टेयर रोपे जाते हैं बीज की बुवाई के लिए पंक्ती से पंक्ती की दूरी 50-60 सेन्टीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 10-15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए.

बुवाई का समय: उत्तरी क्षेत्र- फरवरी-मार्च
पूर्वी क्षेत्र- जनवरी से सितम्बर मध्य, पश्चमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र- सालभर।

खाद एवं उर्वरक: बेबी कॉर्न की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए मृदा जाँच के आधार पर उचित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए 130-150 किलो ग्राम, 50-60 किलो ग्राम फास्फोरस तथा 40-50 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति है क्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए मक्का की तरह फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 33क्र मात्रा बुवाई के समय खेत में बराबर से मिला देना चाहिए तथा नाइट्रोजन की 33क्र मात्रा 25-30 दिन के बाद तथा शेष मात्रा को नरमंजरी निकलते समय देना चाहिए।

सिचाई: बर्सत ऋतु में उगे रई फसल में 8-10 दिन के अन्तराल पर लगातार सिचाई करते रहना चाहिये खरीफ के मौसम में वर्षा न होने पर आवश्यकतानुसार सिचाई करते रहना चाहिए.

फसल सुरक्षा: अच्छी गुणवत्तापूर्ण उपज लेने के लिए जैविक दवाओं जैसे नीम से बनी ह्राओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अपरिहार्य में फ्यूराडान (3 जी) 30 किलोग्राम अथवा फोरेट (10 जी) 10 किलोग्राम प्रति हैक्टेअर की दर से 10 दिन के अन्तराल के बाद कीड़ो को रोकने के लिए छिडकाव करना चाहिए।

प्रमुख प्रभेद: बेबी कॉर्न की अच्छी उपज हेतु अच्छे प्रभेदो का चयन बहुत महत्वपूर्ण है बी. एल. 41, एम. ई. एच-133, एम.इ. एच-144, पूसा, अर्ली हाइब्रिड-1, पूसा अर्ली हाइब्रिड-2, पूसा अर्ली हाइब्रिड-3, आदि बेबी कॉर्न की प्रमुख प्रजातियां हैं।

उपयुक्त जलवायु: मक्के की तरह बेबी कॉर्न की फसल को भी भारत के विभिन्न क्षेत्रो में उगाया जा सकता है। इसकी अच्छी खेती के लिए अनुकूलतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आस-पास होना चाहिए। उत्तर भारत में अधिक गर्मी के समय तापमान बढ़ने से भुट्टे का विकास तेजी से होता है, जिसके कारण कोमल अवस्था में भुट्टे की गुणवत्ता में गिरावट आने लगती है।

भूमि: इसकी खेती मक्के के ही भाँती वलुई दोमट से लेकर भारी मृदा तक सभी प्रकार की भूमियो में की जा सकती है। अधिकतम पैदावार के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमे जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिस मृदा का पी एच मान 6-7 के बीच हो अच्छी मानी जाती है। भूमि में जल निकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

भूमि की तैयारी: गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले एक बार गहरी जुताई करके 2-3 बार हैरो या कलीवेटर से जुताई करते हैं जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है।

बीज दर: बीज की मात्रा में फसल बोने का उद्देश बोने का समय तथा विधि आदि कारणों पर निर्भर करती है। मक्के की तुलना में बेबी कॉर्न को थोड़ी अधिक मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसे कम समय के लिए औसतन 30-35 किलो ग्राम प्रति हक्टेयर बीज पर्याप्त होता है।

नर मंजरी तोड़ना: मक्के की फसल में बेबी कॉर्न की उपज लेने के लिए इसमें महतवपूर्ण कार्य नर मंजरी को तोड़ना होता है। पौधों में फूल आने से पहले ही नर मंजरी को तोड़ देना चाहिए नर मंजरी को तोड़ने से अधिक भुट्टो का उत्पादन होता है तथा परागण न होने से भुट्टे की गुणवत्ता भी खराब नही होती है।

तुड़ाई: बेबी कॉर्न की फसल पर तुड़ाई के समय का बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि तुड़ाई में एक दिन की भी देरी होने से कोमलता खत्म होने लगती है। जिससे गुणवत्ता में कमी आ जाती है।

ताजे बाजार के लिए कोमल भुट्टे से झुआ निकलने से पहले तुड़ाई करना चाहिए तथा प्रसंस्करण के लिए भुट्टे की तुड़ाई सिल्क निकलने के 2-3 दिन बाद करनी चाहिए मूलायम भुट्टे की तुड़ाई बोने के 47-50 दिन बाद कर सकते है। इन्हें प्रतिदिन सावधानी के साथ तोड़ना चाहिए जिससे पत्तियां व तनों को नुकसान न हो भुट्टों को छीलकर बाजार में बेचना चाहिए। सामान्यत: अच्छी प्रजातियों में 45-55 दिन की फसल अवधि में 6-7 तुड़ाई हो जाती है। फसल की अवधि रबी के मौसम में 10-15 दिन बढ़ सकती है।

उपज एवं शुद्ध लाभ: सिंचित दशाओं में संकर प्रजातियों में 60 -80 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर तक बिना छिले हुये भुट्टो के अतिरिक्त 250-300 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर हरे पौधों की उपज प्राप्त होती है। जिसे पशुओं के चारे साइलेज या हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

बेमौसमी सब्जियों की खेती कर मालामाल हो जाइए...

पॉलीहाउस तकनीक से खुले वातावरण की अपेक्षा उच्च गुणवत्तायुक्त एवं ज्यादा मात्रा में किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर सकते है। बदलते मौसम के कारण सब्जियों की पैदावार व गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण किसानों को खुले वातावरण में पैदा की गई सब्जियों से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पता है। वर्षा ऋतु में एवं ग्रीष्म ऋतु में खुले में उगाई गई सब्जियों पर बीमारियों व कीटों में विशेषकर विषाणु रोग फैलाने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होता है।

गुणवत्तायुक्त एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉलीहाउस तकनीक एक वरदानः पॉलीहाउस एक घर नुमा ढांचा होता है जो यूवी. प्रतिरोधी पॉलीथिन की शीट से ढका होता है। इन पॉलीहाउस में कुछ चयनित ग्रीष्मकालीन बेमौसमी सब्जियों व उनकी चयनित केवल संकर किस्मों से अधिक अच्छी गुणवत्ता की पैदावार संभव है। निचले एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलीहाउस में उगाई जाने वाली केवल तीन ही बेमौसमी फसलें है शिमला मिर्च, टमाटर और पार्थिनोकार्पिक खीरा है।

सर्दियों में गर्मीः पॉलीहाउस में सर्दियों में भी बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी रहती है। इसलिए इसे सर्दी की ऋतु में भी गर्मी की फसलों जैसे शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा उत्पादि उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

गर्मियों में ठंडाः देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलीहाउस को गर्मियों में ठंडा रखने में कम लागत आती है तथा इन क्षेत्रों में सब्जी की बेमौसमी निरंतर उपलब्धता एवं उच्च गुणवत्ता हेतु प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस विशेष रूप से उपयोगी है।

अधिकतर ग्रीष्मकालीन पॉलीहाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए औसत तापमान 18-25 डिग्री सेल्सियस चाहिए जो की इन क्षेत्रों में खुले वातावरण में अधिक समय तक नहीं रहता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में पॉलीहाउस में सब्जियां उगना व्यवहारिक एवं लाभप्रद है।

पॉलीहाउस में सब्जियों की सफल खेती हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए...

❖मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के किसान पतझड़-सहित व बर्सात ऋतु में बेमौसमी धनियां, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मटर इत्यादि को केवल पॉलीहाउस में पूर्ण रूप से लगभग सारा साल उगा सकते है, लेकिन इस बात का किसान ध्यान रखें की इन फसलों से उन्हें आमदनी केवल बेमौसम उत्पादन से ही संभव है।

❖पॉलीहाउस में केवल अनियमित बढ़वार वाली संकर किस्में व रोग प्रतिरोधी किस्मे ही लगाएं तथा शीर्षनोचन एवं काट-छांट पर विशेष ध्यान दे।

❖पॉलीहाउस के अंदर एवं बहार सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा एवं दरवाजा हमेशा बंद रखें।

❖ड्रिप-सिंचाई विधि द्वारा तथा फर्टिगेशन (खाद-पानी) का विशेष ध्यान रखें तथा उपयुक्त समय पर सिंचाई व तरल खाद फल बनने के बाद देते रहें।

❖दोहरा दरवाजा, किनारे व ऊपर मलमल के

जाले (40-50 मैश) का प्रयोग करे तथा पॉलीहाउस के ऊपर रोलिंग टाइप के हरे छायादार जले 50त्न का उपयोग अप्रेल से सितंबर तक आवश्यकतानुसार 11 बजे (सुबह) से 3 बजे (शाम) तक करें। ध्यान रखें पॉलीहाउस में दिन का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उपन न जायें।

❖परिवर्तित प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस प्राय: बेमौसमी सब्जियों जैसे मिर्च, टमाटर एवं खीरे की व्यापारिक खेती के लिए उपयुक्त है।

पॉलीहाउस में शिमला मिर्च की खेती..

पॉलीहाउस में किसान आजकल रंगीन शिमला मिर्च उगा रहे हैं जो महानगरों व छोटे शहरों में अच्छी कीमत पर बिक जाती है तथा किसान अधिक आमदनी अर्जित कर रहें है। शिमला मिर्च के सकल उत्पादन के लिए आवश्यक है कि पॉलीहाउस उत्पादक ऐसी संकर किस्मों का चयन करें जिनका आकार अच्छा हो तथा चार लोब हो एवं आकार घंटीनुमा हो। चयनित प्रजातियों में अच्छी अवधि तक मंडीकरण योग्य फल देने की क्षमता का होना आवश्यक है। किसानों को चाहिए कि वे शिमला मिर्च की संकर प्रजाति को उगाने से पहले क्षेत्र के अन्य पॉलीहाउस उत्पादकों से विचार-विमर्श अवश्य करें ताकि उनसे अच्छी पैदावार देने वाली संकर किस्मों का व्यवहारिक ज्ञान हो।

क्यारी बनाना : 85-100 से.मी. चौड़ी तथा 25-20 से.मी. ऊँची क्यारियाँ बनानी चाहिए और दो क्यारियों के बिच की दूरी 50 से.मी. रखनी चाहिए जिससे काम करने में आसानी हो। क्यारियों को रोगाणु रहित बनाने के लिए 5त्न फॉर्मलीन 40त्न का घोल बनाकर उसे 3-4 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालकर ड्रैंच करें। पौध रोपण तभी करें जब फार्मलीन की गंध समाप्त हो जाये।

पौध तैयार करना एवं रोपाई : शिमला मिर्च का बीज महंगा होने के कारण पौध संरक्षित तरिके से पॉलीहाउस में मिट्टी रहित प्लास्टिक ट्रे में तैयार करनी चाहिए व जमीन से उठी हुई क्यारियों में से जो पहले से उपचारित हो तथा इसे कीटरोधी नेट द्वारा अच्छी तरह ढका गया हो का उपयोग किया जा सकता है। 20-25 दिनों में तैयार पौध को अच्छी तरह से तैयार भूमि में उठी हुई क्यारियों में रोपाई करें। निचले एवं मध्यवर्गीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष में शिमला मिर्च की रोपाई जनवरी-फरवरी और जुलाई-अगस्त दो बार कर सकते हैं। लेकिन ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च-अक्टूम्बर तक शिमला मिर्च की पौध की रोपाई लाइनों में करें जिनकी दूरी 40 से 50 से.मी. और पौध से पौध की दुरी 30 से 40 से.मी. रखें।

सिंचाई एवं फर्टिगेशन : पॉलीहाउस या नेट हाँउस में उगाई गई फसल में ड्रिप विधि से सिंचाई व उर्वरक देना ठीक रहता हैं। गर्मियों में प्रत्येक दिन सर्दियों में हर दूसरे दिन सिंचाई करनी चाहिए। पानी में कोई भी घुलनशील मिश्रित खाद या उर्वरक जैसे पॉलिफिड (19:19:19) 1.5 कि.ग्रा. प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सप्ताह में दो बार सिंचाई के साथ करें। फर्टिगेशन रोपाई के बाद तीसरे सप्ताह में शुरू करें व अंतिम तोड़ाई से 15 दिन पहले बंद कर दें। यदि पॉलिफिड 19:19:19) एन.पी.के. का प्रयोग करें तो 2.0-2.2 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से सप्ताह में दो बार पानी का घोल प्रत्येक फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त हैं। 7 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी तथा प्रत्येक पौधे के साथ अवस्था के अनुसार 100 से 250 मि.लीटर घोल डालें।

पौधों की कटाई, छटाई तथा सहारा देना

❖प्रजाति के अनुसार 9 से 13 पत्ते आने के बाद मुख्य फूल या क्राउन बड को निकल दें।

-पॉलीहाउस की ऊंचाई के अनुसार 2 या 4 टहनियां या शाखाएँ रखें।

❖प्रत्येक नोक पर एक फूल या दो पत्तें रखें बाकि फूल या पत्ते निकाल दें तथा अतिरिक्त शाखाओं की निरंतर कटाई या छटाई करें।

❖प्रत्येक शाखा को नारियल की रस्सी या सुतली से लपेटे तथा इसी के सहारे ऊपर की दिशा में रस्सी या सुतली को घुमाते हुये ट्रेनिंग करें।

पॉलीहाउस में टमाटर की खेती

पॉलीहाउस में विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर उत्पादन की अपार संभावनाए हैं क्योंकि खुले वातावरण में तैयार टमाटर की फसल कम गुणवत्ता व कम पैदावार वाली होती हैं तथा बीमारी व कीटों से बचाने के लिए किसान इन फसल पर अत्यधिक छिड़काव करते हैं जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होता हैं तथा लोगों को विभिन्न घातक बीमारियाँ होने का डर बना रहता हैं।

शिमला मिर्च की तरह टमाटर में भी जीवाणु मुरझन रोग का प्रकोप पाया गया हैं तथा इसके सफल उत्पादन के लिए जीवाणु मुरझन ग्रसित क्षेत्रों में इस रोग की प्रतिरोधी संकर किस्में ही लगाये तथा ऐसी संकर किस्मों का चुनाव करें जिनका आकार गोल या उच्च गोल हो तथा इसके फल लम्बी अवधि तक तरोताजा रहें। इसके साथ-साथ चयनित संकर प्रजातियों में ज्यादा दिनों तक मंडीकरण योग्य फल देने की क्षमता का होना भी आवश्यक हैं।

महत्वपूर्ण शस्य क्रियायें: टमाटर की केवल अनियमित बढ़वार वाली संकर किस्में जैसे की अमीशा, नवीन 2000 प्लस (जीवाणु मुर्झान रोग प्रतिरोधी) किस्में ही लगाए। टमाटर की भी मांग बढ़ रही हैं जिसके लिए किसान बी.एस.एस.- 366 किस्म (जीवाणु मुरझन रोग सहनशील लगाए)।

पॉलीहाउस की ऊंचाई के अनुसार 2 टहनियां लेकर रस्सी या सुतली से ट्रेनिंग करें तथा अतिरिक्त टहनियों की काट-छट करते रहें।

सिंचाई : ड्रिप विधि से सिंचाई करें तथा तरल पौधे लगाने के तीन सप्ताह बाद भूमि के कम उपजाऊपन के अनुसार सप्ताह में एक या दो बार दें तथा अंतिम तोड़ाई से 15 दिन पहले तरल खाद बंद कर दे।

खीरा की खेती पॉलीहाउस में..

खीरे का उत्पादन अभी तक खुले वातावरण में ही बरसात ऋतु में किया जाता रहा हैं किन्तु फल मक्खी के अत्यधिक प्रकोप के कारण इसकी सफल खेती के लिए किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। सर्दी के मौसम व आरम्भिक बसंत व ग्रीष्म ऋतु में खीरे की उपलब्धता बाजार में कम होने के कारण इसकी खेती किसानों को इस समय ज्यादा लाभप्रद हो सकती हैं। अतः निचले व मध्य क्षेत्रों के पॉलीहाउस उत्पादक कम खर्च से परिवर्तित प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस में खीरे की दो फसलें (बसंत तथा पतझड़ शीत) उगा सकते हैं तथा बाजार में उस समय खीरे के भाव भी ठीक होते हैं तथा कीटनाशकों व फफूंदनाशकों का छिड़काव किये बिना ही पॉलीहाउस में इसका सफल उत्पादन कर सकते हैं।

पॉलीहाउस में खीरे के सफल उत्पादन के लिए सस्य क्रियायें

❖ पॉलीहाउस में खीरे के सफल उत्पादन के लिए पार्थिनोकार्पिक किस्में जिनमे बिना परागकण के फल तैयार होते हैं जैसे की क्यानख, पी.सी.पी.एच.-5, इसेटिस, मल्टीना, मनसोर, हसन इत्यादि ही लगाए।

❖ पॉलीहाउस की ऊंचाई के अनुसार एक या दो टहनियां लेकर रस्सी या सुतली से ट्रेनिंग करें तथा अतिरिक्त टहनियों की काट-छाट करते रहें।

❖पहली पांच गांठों तक फूलों को निकाल दें।

सिंचाई : ड्रिप विधि से सिंचाई करें तथा तरल खाद पौधे लगाने के तीन सप्ताह बाद भूमि के उपजाऊपन के अनुसार सप्ताह में एक या दो बार दें तथा अंतिम तोड़ाई से 15 दिन पहले तरल खाद देना बंद कर दें। अतः किसान भाई पॉलीहाउस तकनीक अपनाकर सिर्फ बेमौसमी सब्जिया ही नहीं अपितु विषाणु रहित बढ़िया गुणवत्ता वाली सब्जियां उगाकर अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आवश्यक हैं की किसान कम लागत वाली तकनीक को अच्छी तरह जाने ताकि कम से कम खर्चों में उच्च गुणों वाली सब्जियों का उत्पादन कर सकें। बाजार की उच्च मांग के अनुसार तथा खुले वातावरण के खतरों से बचने के लिए तथा सिमित जगह पर पॉलीहाउस में इन फसलों की खेती करना एक अच्छा विकल्प हैं।

स्मार्ट खेती को बढ़ावा दे रहीं कंपनियां

नई दिल्ली (विसं)। देश में स्मार्ट खेती का चलन बढ़ रहा है और अब छोटे तथा सीमांत किसानों को भी इसका फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। स्मार्ट खेती के क्षेत्र की दिग्गज अंतरराष्ट्रीय कंपनियां छोटे और सीमांत किसानों की जरूरत के हिसाब से नए उपाय पेश कर और विशेषज्ञ मॉडल अपनाकर उनकी मदद कर रही हैं।

इस तरह की खेती में कम संसाधनों के साथ ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जीपीएस, जीएनएसएस और ड्रोन के इस्तेमाल से इस बात का सटीक अनुमान लगाया जाता है कि अधिकतम पैदावार के लिए कौन सी फसल और मिट्टी चाहिए तथा फसल की बर्बादी को कम कैसे किया जाए। साथ ही फसल कटने के बाद ही गतिविधियों में भी इसका उपयोग होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि उत्पादों का भंडारण वहां हो, जहां मौसम और उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम इस्तेमाल होता है। हालांकि स्मार्ट खेती पिछले कुछ समय से हो रही है, लेकिन अभी तक कॉर्पोरेट फॉर्म और बड़ी जोत वाले किसानों में इसका इस्तेमाल करने की कुव्वत थी। इसकी सीधी वजह यह थी कि इसके लिए जरूरी उपकरण खरीदने और लगाने में बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है तथा अधिकतर उपकरणों का आयात किया जाता है। यही कारण है कि देश में इसका प्रसार नहीं हो पाया।

ट्रिंबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिज इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन अय्यर ने कहा, 'हम किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक उपकरण आदि किराये पर देने का मॉडल अपना रहे हैं और मूल उपकरण बनाने वाले स्थानीय निर्माताओं को भी अपने साथ ले रहे हैं। उनकी मदद से हम उत्पादों को आगे बढ़ा सकते हैं।' ट्रिंबल भारत में लॉजिस्टिक्स, नौवहन और परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉल्यूशन मुहैया कराती है और अब उसकी नजर स्मार्ट खेती में अपने कारोबार का विस्तार करने पर है। भारत में अधिकतर छोटे किसान हैं और छोटी जोत पर निर्भर हैं। उनकी हालत सुधरी तो स्मार्ट खेती का प्रचलन जोर पकडने लगेगा और यह अरबों डॉलर का उद्योग बन जाएगा।

कई राज्य सरकारें अपने सब्सिडी कार्यक्रम में स्मार्ट खेती के उपकरण शामिल करने पर विचार कर रही हैं। भारत में कॉर्पोरेट खेती का चलन बढ़ रहा है जो हमारे उपकरण और सेंसर खरीद सकती हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमारे पास विशेष सदस्यता मॉडल है। हम सहकारिता संघों के साथ भी काम कर रहे हैं जो हमारे उपकरण किराये पर ले सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के अलावा कई देसी स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। वे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, आईओटी और ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल कर रही हैं।

अगले दो साल में 415 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा : राधा मोहन सिंह

नई दिल्ली (विसं)। किसानों को उनके उपज मूल्य में पारदर्शीता दिलाने और व्यापार को बढ़ावा दिलाने के लिए लॉन्च की गई इ-नाम योजना में अगले दो साल में 415 बाजार और जुड़ जाएंगी। इस संख्या में इस वर्ष 200 मंडियां और अगले वर्ष 215 मंडियां और जोड़ी जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के इस प्लेटफार्म पर 16 राजायों के अब तक 1.14 करोड़ किसान पंजीकरण करा चुके हैं। इस विषय पर केंद्रिय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि राजग की पिछली सरकार ने 2003 में कृषि विपणन क्षेत्र में सांकेतिक सुधार मॉडल अधिनियम बनाया था और इसमें ई-नाम, ई-व्यापार के साथ संविदा खेती और एकीकृत व्यापार लाइसेंस की व्यवस्था शामिल थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा की वर्ष 2014 तक इसमें कुछ कार्य नहीं हुआ और 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस दिशा में काम तेज किया गया। कृषि मंत्री ने बताया कि बाद में सरकार के द्वारा ई-नाम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार लांच किया और अब तक इससे 585 मंडियों को जोड़ा जा चुका है। सरकार इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म से कुल 1000 मंडियों को जोड़ना चाहती है। इसके अतिरिक्त सरकार देश की 22 हजार ग्रामीण हाटों को विकसित कर इन्हें ई-नाम प्लेटफार्म के साथ एकीकृत करने की दिशा में भी काम कर रही है। वहीं एक प्रश्न के जवाब में कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 1.14 करोड़ किसानों के अतिरिक्त ई-नाम प्लेटफार्म पर कृषि क्षेत्र में ट्रेडिंग करने वाले एक लाख 14 हजार व्यापारी भी अपना पंजीकरण करा चुके हैं।

कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ी आमदनी : नाबार्ड

नई दिल्ली (विसं)। भारत में खेती बाड़ी से जुड़े करीब 53 प्रतिशत परिवार कुछ न कुछ कर्ज से दबे हैं। नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक यह आंकड़े 2012-13 और 2015-16 के बीच कम नहीं हुए हैं। इस अवधि के दौरान प्रति परिवार औसत कर्ज की मात्रा बढ़ी है। नाबार्ड की ओर से सर्वे के मुताबिक 2012-13 और 2015-16 के बीच भारत के किसानों की सालाना औसत आमदनी 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है। अगर यह आंकड़े सही हैं तो किसानों की 2022 तक आमदनी दोगुनी करने पर बनी उच्चाधिकार प्राप्त सरकारी समिति की सालाना वृद्धि दर की उम्मीद से ज्यादा है। नैशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी (एनआरएए) के सीईओ अशोक दलवी की अध्यक्षता में बनी समिति ने कहा है कि किसानों की वास्तविक आमदनी में 10.4 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर होनी चाहिए जिसेस 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। नाबार्ड के सर्वे से पता चलता है कि 2015-15 के दौरान 29 राज्यों में से 19 राज्यों के किसानों की आमदनी देश के औसत की तुलना में ज्यादा थी और 15 राज्यों की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर 2012-13 से 2015-16 के बीच 10.5 प्रतिशत से ज्यादा रही है। सर्वे में कहा गया है, 'कृषि परिवारों की आमदनी में खेती से आमदनी की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत है, जबकि गैर कृषि वाले परिवारों की आमदनी में मजदूरी की हिस्सेदारी करीब 54 प्रतिशत है।'

कृषि विभाग किसानों को दिलाएगा रियायती दर पर यंत्र

मिर्जापुर। जिले के किसानों को रियायती दर पर कृषि यंत्र मुहैया कराने के लिए यंत्रीकरण माह शुरु किया है। इस माह के तहत पंजीकृत किसान कोई भी कृषि यंत्र रियायती दर पर खरीद सकते हैं। कृषि विभाग अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में भुगतान करेगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए जिले के सभी कृषक कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। कृषकों का चयन प्रथम आओ, प्रथम पाओ योजना के तहत किया जाएगा। उप निदेशक कृषि एके उपाध्याय ने बताया कि चयनित कृषक को चयन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर यंत्र क्रय करके वेबसाइट पर अपलोड करना होगा तथा मूल बिल व आवेदन पत्र उप कृषि निदेशक, पिपराडाड़ के कार्यालय में जमा करना होगा।

यूपी में अब नीम के पौधे लगवाएगी सरकार

लखनऊ (विसं)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 5 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण किया गया है और सहकारिता विभाग द्वारा जनपद गोरखपुर में एक लाख नीम के पौधे लगाने का जिम्मा लिया गया है। वृक्षारोपण पर्यावरण के प्रति सजगता का नया संकेत है। मुख्यमंत्री ने कुस्महो वन में तथा जिला सहकारी फडरेशन कम्पाउंड में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। खुद पौधा लगाने के बाद सभी से अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया तथा वृक्षों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि वन टांगिया के जीवन का उन्नयन करने हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है और इसके लिए योजनाएं भी संचालित की है। मुख्यमंत्री ने जिला सहकारी फडरेशन कम्पाउंड में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित वृहद नीम वृक्षारोपण व सहकार सम्मेलन में जनपद के 5 कृषकों को नीम का पौधा प्रदान किया तथा समस्त जनों से आह्वान किया कि वे नीम का पौधा अवश्य लगायें।

भारत में पहली बार दिखा मक्का को तबाह करने वाला अमेरिकी कैटरपिलर

चिकबल्लापुर (कर्नाटक) (विसं)। देश के मक्का किसानों के लिए एक बुरी खबर है। वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में एक ऐसा कैटरपिलर देखा है जो मक्का की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मूलत: अमेरिका में पाया जाने वाला यह कीट एशिया में पहली बार देखा गया है। इससे पहले यह पिछले साल अफ्रीका महाद्वीप के देशों में तबाही मचा चुका है। इसका भारत में पाया जाना इसलिए और भी चिंता की बात है क्योंकि मक्का के अलावा यह धान, कपास और गन्ना समेत 180 पादप प्रजातियों को बर्बाद कर सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिकों ने सर्वे में देखा कि फॉल आर्मीवर्म नामका यह कीड़ा दक्षिणी कर्नाटक के चिकबल्लापुर इलाके की 70 फीसदी मक्के की फसल को प्रभावित कर चुका है। आईसीएआर के सहयोगी संगठन नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इन्सेक्ट रिसोर्सेज के वैज्ञानिकों डॉ. एएन शैलेश, डॉ. एसके जलाली ने इस कीट का अध्ययन करके बताया, पीले और भूरे रंग का यह कीट बहुत तेजी से अंडे देता है और बड़ी तेजी से फैलता है। आईपीएम के जरिए कम खर्च में कीड़ों और रोगों से फसल बचाइए ऐसी भी खबरें हैं कि अब तक यह कीट पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक पहुंच चुका है। लेकिन वैज्ञानिक ठीक तौर पर यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह भारत तक आया कैसे। यह भी मुमकिन है कि यह प्रभावित इलाके से किसी इंसान के साथ चला आया हो या फिर अंडे देने वाला इसका शलभ वाला स्वरूप हवा की धाराओं के साथ भारत पहुंचा हो। माना जाता है कि इस अवस्था में यह एक रात में हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन इस कीट की रोकथाम के लिए अब तक अपने बजट से 21 मिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से परहेज आर्मीवर्म कैटरपिलर अफ्रीका के 44 देशों में मक्का की खेती को प्रभावित कर चुका है। एफएओ ने साल 2017 में चेतावनी दी थी कि इसकी वहज से इन देशों के 30 करोड़ निवासियों पर भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। इस कीड़े को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता इसलिए इस पर रासायनिक कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भारत में पहले भी कीटनाशकों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से किसानों को न केवल सेहत का नुकसान हुआ बल्कि आर्थिक बोझा बढ़ने से बहुतों ने आत्महत्या भी की। जैविक कीटनाशक ज्यादा कारगर अफ्रीका का अनुभव बताता है कि इस कीड़े को या तो हाथ से मारा जाए या फिर इस पर नीम और तंबाकू से बने जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाए।

Hindchem Corproation

AMINO+HUMIC SHINY BALLS
FERROUS SULPHATE19%
MAGNESIUM SULPHATE 9.6%
FERROUS EDTA12%
E.D.T.A. ACID
CAMPHOR
SODIUM BICARBONATE
EDTA DISODIUM
CITRIC ACID MONOHYDRATE
MANGANESE SULPHATE 30.5%
SULPHUR 90% -80WDG
BORON 20%
BRONOPOL 25%
PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

एफएओ ने कीट के संक्रमण पर चेताया

मुंबई (कासं)। लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव की आशंका के मद्देनजर अमेरिका के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने 'फाल आर्मीवर्म' कीट के बढ़ते जोखिम को लेकर सावधान किया है। यह कीट फसलों पर हमला करता है और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैल रहा है। इस साल मई में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में पहली बार पता चलने के बाद फाल आर्मीवर्म कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएचएस) के प्रदर्शन क्षेत्र में उगाई गई मक्का की पूरी फसल को नष्ट कर चुका है। अमेरिकी मूल का यह फाल आर्मीवर्म कीट पहले ही पूरे अफ्रीका में फैल चुका है। वहां यह कीट पहली बार 2016 में पाया गया था। 2018 की शुरुआत तक अफ्रीका के 10 राज्यों और प्रदेशों (जिनमें ज्यादातर महाद्वीप के उत्तर में हैं) को छोड़कर पूरे इलाके में इसके संक्रमण की सूचना मिली है और इस कीट ने मक्का तथा ज्वार के लाखों हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसके असर को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र की अनुकूल उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिहाज से इस कीट में काफी लंबी दूरी (एक रात में 100 किलोमीटर) की उड़ान भरने की क्षमता है और यह साल भर फसल बरबाद कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि फसलें और खरपतवार हमेशा इस कीट के निशाने पर रहती हैं। एशिया के अन्य हिस्सों में भी फाल आर्मीवर्म का संक्रमण पाया गया है। एफएओ द्वारा जारी किए गए एक परामर्श में कहा गया है कि फाल आर्मीवर्म एशिया में छोटे पैमाने के लाखों किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है क्योंकि इस बात की काफी संभावना है कि फसल भक्षण करने वाला यह कीट भारत से आगे हमला कर सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण चीन में इस बात का खतरा सबसे अधिक है। फाल आर्मीवर्म मक्का समेत 80 अन्य फसलों को खा सकता है जिनमें चावल, सब्जियां, मूंगफली और कपास भी शामिल हैं। एफएओ के सहायक महानिदेशक और एशिया-प्रशांत के क्षेत्रीय प्रतिनिधि कुंभवी कादिरेसन ने कहा कि एशिया के मक्का और चावल उत्पादकों पर फाल आर्मीवर्म का विनाशकारी प्रभाव हो सकता है जिनमें से ज्यादातर छोटे पैमाने वाले ऐसे किसान हैं जिनकी आजीविका उनकी फसलों पर निर्भर होती है। यह एक ऐसा खतरा है जिसकी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं।

एशिया में छोटे पैमाने पर खेती करने वाले किसान इस क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत भाग में खेती करते हैं। यहां चावल और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन और उपभोग किया जाता है। एशिया में प्रति वर्ष 20 करोड़ से अधिक हेक्टेयर में मक्का और चावल की खेती की जाती है। विश्व में चीन मक्का का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व के चावल का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन तथा उपभोग एशिया-प्रशांत क्षेत्र में किया जाता है।

फूड प्रोसेसिंग में उतरी इफको

नई दिल्ली। उर्वरक कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव (इफको) अब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उतर रही है। उसने स्पेन की कंपनी कॉजेलादोस डी नवारा के साथ मिलकर लुधियाना में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए संयुक्त उद्यम 325 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस परियोजना से पंजाब में प्रत्यक्ष तौर पर 400 लोगों को रोजगार मिल सकेगा, वहीं 5,000 लोग अप्रत्यक्ष तौर जुड़ सकेंगे। कॉजेलादोस डी नवारा 220 मिलियन डॉलर की कंपनी है। कंपनी सब्जियों, फलों, जड़ी-बूटियों और तैयार व्यंजनों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करती है।

संयंत्र से किसानों की मिलेगी काफी मददः इफको के एमडी डॉ. यूएस अवस्थी के अनुसार कंपनी के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उतरने से वह काफी खुश हैं। इससे किसानों का भला होगा। इफको में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कैसे किसानों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार की वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य में योगदान देने जैसा है। 2020 तक फोजन आलू, गोभी और मटर जैसे प्रसंस्कृत उत्पादों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस संबंध में एमओयू हो गया है।

अक्टूबर से 15 दिन में मिलेगा किसानों को फसल का बीमा

नई दिल्ली (विसं)। केंद्र सरकार अक्टूबर में ऐसा एप लॉन्च करने जा रही है जो किसानों को फसल बीमा दिलाने की राह बेहद आसान बना देगा। इस एप का नाम 'क्रॉप लॉस रिपोर्टिंग एप' है। कृषि विभाग के मुताबिक 5 करोड़ किसानों ने फिलहाल फसल बीमा करा रखा है। एप के जरिए किसान को 72 घंटे के भीतर प्रभावित फसल की फोटो भेजनी होगी। इसके बाद बीमा कंपनियां 10 दिन के अंदर सर्वे करेंगी। इसके 15 दिन के अंदर बीमा का भुगतान हो जाएगा। अगर बीमा कंपनी ने समय से भुगतान नहीं किया तो बाद में उसे 12 फीसदी ब्याज के साथ रुपए चुकाने होंगे। फिलहाल किसानों के पास फोन या वेबसाइट से शिकायत करने का विकल्प मौजूद है।

पहले करना होगा एप में रजिस्ट्रेशनः सबसे पहले गूगल प्लेस्टोर से एप डाउनलोड कर उसमें खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए उसमें सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा ताकि संबंधित किसान की पहचान वेरीफाई हो सके। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा ताकि कोई गलत तरीके से शिकायत न दर्ज कर सके। इसके बाद किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

आईआईटी बॉम्बे का 56वां दीक्षांत समारोह

मुंबई (कासं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आईआईटी बॉम्बे के 56वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को 1000 करोड़ रु देने का ऐलान किया। मोदी ने आईआईटी को न्यू इंडिया का स्तंभ बताते हुए इसे इंडियन इन्स्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताया। छात्रों से कहा- यहां से निकलने के बाद आपकी असल परीक्षा होगी, इसके लिए शुभकामनाएं। आप असफलता के उत्खनन को मन से निकालें और एक्सिपरेशन पर फोकस करें। यह आईआईटी बॉम्बे का हीरक जयंती वर्ष है। देश को आईआईटी पर गर्व है और यह दुनिया में भारत के ब्रांड के तौर पर उभरा है। आईआईटी को दुनिया स्टार्टअप की नर्सरी के तौर पर मान रही है। भारत आज स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है।

केरल की बाढ़ में डूबी कृषि

चेन्नई (विसं)। केरल में मॉनसूनी बारिश की वजह से करीब छह अरब रुपये का नुकसान हो चुका है। किसानों के शुरुआती अनुमान में यह बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस बारिश से अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इसलिए उद्योग को इस बात का डर है कि इससे होने वालानुकसान बढ़ सकता है। एसोसिएशन ऑफ प्लांटर्स ऑफ केरल के सचिव अजीत बालाकृष्णन ने कहा कि सिर्फ फसल का नुकसान ही तकरीबन छह अरब रुपये का होगा। अभी तक इस बात का पता नहीं है कि बुनियादी ढांचे आदि के हिसाब से कुल कितना नुकसान होगा।

चाय क्षेत्र में 50 प्रतिशत (करीब 1.50 अरब रुपये) फसल क्षति के आसार हैं, जबकि वयनाड में भूस्खलन की वजह से 100 एकड़ की कृषि के नुकसान का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है। रबर की फसल में करीब 40 फीसदी का नुकसान होने की आशंका है जबकि पानी में डूबी इलायची की खेती को तकरीबन तीन अरब रुपये की क्षति हो सकती है।

यू एस एग्रोकेम प्रा.लि.

Wholesale Supplier

सूक्ष्म तत्व मिश्रण तरल एवं दानेदार

व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है

प्लाट नं. बी-81, 82, नीलगिरी कॉलोनी, रोड नं. 9 के सामने, वीकेआई एरिया, जयपुर-302013 (राजस्थान)

E-mail : suresh@hindchem.com, Contact : 9004744077

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होगी काजू की खेती, अफ्रीका से मंगाकर 150 हेक्टेयर में बोए जाएंगे बीज

बैतूल (विसं)। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जल्द ही काजू की खेती की जाएगी। इसकी तैयारी हो गई। प्रयोग के तौर पर पहले 150 हेक्टेयर जमीन पर फसल बोई जाएगी। अफ्रीका से काजू का बीज मंगाया गया है। बैतूल प्रदेश का पहला जिला होगा जहां काजू उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से शुरू किया जाएगा। काजू संचालनालय के डायरेक्टर डॉ. वेंकटेश ने जिले का तीन दिवसीय दौरा कर तैयार की रिपोर्ट में यह बात कही है। डॉ. वेंकटेश ने उद्यानिकी विभाग की उपसंचालक डॉ. आशा उपवंशी के साथ जिले में तीन दिन तक भ्रमण किया था। डॉ. वेंकटेश ने बताया कि बैतूल में काजू की वेंगरूला- 47 प्रजाति जलवायु को सूट करती है। भारत सरकार ने अफ्रीका से काजू की प्रजातियों के बीज मंगाने की तैयारी की है। यह बीज आता है तो इसे किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। जिले में काजू की खेती की भरपूर संभावनाएं हैं। फिलहाल, 150 हेक्टेयर जमीन पर काजू की खेती करने का टारगेट तय किया गया है। वर्तमान में तीन विकासखंडों घोड़ाडोंगरी, शाहपुर और चिचोली में ही काजू की खेती होती है। डॉ. वेंकटेश ने बताया कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध रत्नागिरी में भी हापुस और अल्फांसो आम की जगह काजू का उत्पादन किसान कर रहे हैं। अनुपजाऊ जमीनों से भी वे बेहतर आमदनी कर रहे हैं। उपसंचालक उद्यानिकी डॉ. आशा उपवंशी ने बताया कि महाराष्ट्र के काजू उत्पादक किसानों को लाकर बैतूल के किसानों को काजू उत्पादन का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

पपीता की व्यवसायिक खेती

उमेश कुमार, डॉ. डी. राम, श्रीकान्त, अतुल कुमार और राजेश कुमार
तोथ छात्र, उद्यान विज्ञान विभाग, प्रोफेसर, उद्यान विज्ञान विभाग, तोथ छात्र, कृषि प्रसार शिक्षा विभाग, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद (उ.प्र.)224229

परिचय: पपीता शीघ्र ही तैयार होने वाला बहुत ही उपयोगी फल है। इसमें बहुत ही पौष्टिक गुण पाए जाते हैं हमारे देश में पपीता गृहवाटिका में उगाना प्रचलित है इसकी पैदावार शीत कटीबन्धीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में की जाती है लेकिन अब इसकी खेती व्यवसायिक रूप में की जाती है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें पपेन एवं पेक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित दवाइयों के बनाने में किया जाता है पपेन पपीते के कच्चे फलो से निकाला जाता है। इसके पौधों को एक बार लगा देने पर दो फास ले ली जा सकती है इनके पौधों की कुल आयु लगभग तीन साल तक होती है।

भूमि एवं जलवायु: पपीता किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है लेकिन इसकी सबसे अच्छी खेती जीवांशयुक्त एवं उचित जल निकास वाली बलुई दोमट एवं दोमट मिट्टी जिस का पी.एच.मान 6.5 से 7.5 में की जाती है।

पपीते की सबसे अच्छी फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है लेकिन समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी अच्छी पैदावार देता है शुष्क गर्म जलवायु में इसके फल अधिक मीठे होते है परन्तु अधिक नमी इसके फलों के गुणों को खराब कर देती है।

उन्नतशील प्रजातियां: गाईनो डायोसिएस- पूसा डेलीसियस, पूसा मजेस्टी, ताइवान, सूर्या, सनराई जसीलो

डायोसिएस: पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, CO-1, CO-2, CO-5, CO-6

संकर प्रजातियां: CO-3: CO-2 X सनराईजसीलो, CO-4: CO-2 X वाशिंगटन, CO-7: पूसाडेलीसियस X कुर्ग हनीड्यू

बीज दर: 250 से 300 ग्राम गाईनो डायोसिएस तथा 400 से 500 ग्राम डायोसिएस प्रजातियॉ प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है।

पौधशाला: पपीते की पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊँची क्यारी या गमले या पोलिथिन बैग में पौधे तैयार करते हैं बीज की बुवाई से पहले क्यारी को 10 प्रतिशत फोर्मेलडीहाइडके घोल का छिड़काव करके उपचारित करते हैं इसके बाद बीज को 1 सेंटीमीटर गहराई एवं 10 सेंटीमीटर दूरी पर बीज को बोते हैं इन पौधों को रोपाई हेतु 60 दिन बाद जब पौधे 15-25 सेंटीमीटर ऊँचे हो जाएँ तब इनकी रोपाई करनी चाहिए।

पौधरोपण: भारत में पपीता की खेती तीन मौसम में की जाती है तथा पौध उसी तरह से 60 दिन पहले तैयार की जाती है सबसे पहले जून एवं जुलाई में, इसके बाद सितंबर अक्टूबर में तथा अंत में फरवरी एवं मार्च में रोपण किया जाता है। दक्षिण भारत में साधारणत: फरवरी मार्च में रोपाई की जाती है खेत में पौधों की रोपाई दोपहर बाद तीन बजे सायं से करनी चाहिए रोपाई के बाद पानी लगाना अति आवश्यक होता है तैयार किये गए गड्ढों में 2 या 3 पौधे थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। जब तक अच्छी तरह से पौधे स्थापित न हो जाये तब तक प्रतिदिन सायं के समय हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा फूल आने पर 10 प्रतिशत नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को काटकर अलग कर देना चाहिए।

पौधों की दूरी: पपीते की लगभग सभी प्रजातियों को 1.8× 1.8 मी. की दूरी पर लगाया जाता है लेकिन पूसा नन्हा प्रजाति को 1.25× 1.25 मी. पर लगाना चाहिए।

खाद तथा उर्वरक: पपीते की अच्छी पैदावार लेने के लिए प्रति पौधा 5-10 किलो ग्राम सड़ी गोबर की खाद तथा 200-250 ग्राम नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश को गड्ढों में अच्छी तरह से मिलाना चाहिए तथा पौधों में चूना तथा बोरोन की कमी हो दूर करने के लिए 0.5 प्रतिशत जिंक सलफेट तथा 0.1 प्रतिशत बोरोन का छिड़काव करना चाहिए।

मिट्टी चढ़ाना: पपीते के पौधों पर मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवस्यक है। पपीते के पौधों की जड़ों के आसपास 30 सेंटीमीटर की गोलाई में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए ताकि पेड़ के पास सिंचाई का पानी अधिक न लग सके तथा पौधे भी गिरने से बच जात हैं।

जल प्रबंधन : पपीते के लिए सिचाई का उचित प्रबंध होना बहुत ही आवश्यक है। गर्मियों में 6-7 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 10-12 दिन के अंतराल पर सिचाई करनी चाहिए तथा वर्षा ऋतु में पानी न बरसने पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहना चाहिए तथा ध्यान रहे की सिंचाई का पानी पौधे के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण: लगातार सिंचाई करते रहने से खेत की मिट्टी बहुत ही कड़ी हो जाती है जिससे पौधों की वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ता है अत: हर 2 सिचाईके बाद थालों की हल की निराइ गुड़ाई कर देनी चाहिए जिससे भूमि में हवा एवं पानी का अच्छा संचार बना रहे।

रोग प्रबंधन: पपीते के पौधों में मोसैक, लीफकर्ल, रिंगस्पाट, जड़ एवं तना सड़न, एन्थ्रेक्नोस आदि रोग लगते हैं इनके नियंत्रण के लिए बोर्डोमिक्सचर 5:5:50 के अनुपात का पेड़ों पर सड़न गलन को खरोंच कर लेप करना चाहिए तथा अन्य रोगों के लिए ब्लैटोक्स 3 ग्राम या डाइथेनएम.-452 ग्राम प्रतिलीटर अथवा मेन्कोजेबवाजिनेब 0.25 प्रतिशत का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए अथवा कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 3 ग्राम या ब्रासीकाल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।

कीट प्रबंधन : पपीते के पौधों को कीटों से बहुत ही कम नुकसान होता है तथा फिर भी कुछ कीड़े लगते हैं जैसे माहू, रेड स्पाईडरमाईट, तथा निमेटोड आदि हैं इनके नियंत्रण के लिए डाईमेथोएट 30 ई.सी. को 1.5 लीटर या फास्फेडान 0.5 मिली. प्रतिलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से माहू आदि का नियंत्रण हो जाता है।

फलों की तुड़ाई: फलों के पकने पर चिड़ियों से बचाना बहुत जरूरी है अत: फल पकने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। जब फलों की ऊपरी सतह पर खरोंच कर देखें तो दूध जैसा तरल पदार्थ जो पानी जैसा निकले और फल का रंग परिवर्तित होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि फल पक गया है और फल को तुड़ाई कर लेनी चाहिए। ध्यान रहे कि फल को तोड़ते समय किसी भी प्रकार को खरोंच या दाग धब्बे आदि न पड़ने पायें नहीं तो फल सड़कर खराब हो जाते हैं।

उपज: पपीता की पैदावार या उसकी उपज के लिए, प्रति पौधा तथा प्रति हैक्टेयर कितनी मात्रा हमारे किसान भाई प्राप्त कर लेते हैं, पैदावार मिट्टी की किस्म, जलवायु और उचित देखभाल पर निर्भर करती है। समुचित व्यवस्था होने पर प्रति पौधा लगभग 35-50 किलो ग्राम फल तथा 15-20 टन प्रति हैक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है।

पैकिंग करना : फलों को सुरक्षित तोड़ने के बाद फलों पर कागज या अखबार आदि से लपेटकर अलग-अलग प्रतिफल को किसी लकड़ी या गत्ते के बॉक्स में मुलायम कागज की कतरन आदि को बिछाकर फल रखने चाहिए और बॉक्स को बंद करके बाजार तक भेजना चाहिए ताकि फल खराब न हों अच्छे भाव बाजार में मिल सके।

गौण बीजीय मसालों की उन्नत प्रजातियां

मसालों के उत्पादन में भारत ने एक मिसाल कायम किया है। भारत के मसालों का पूरे विश्व में बोल बाला है। मसालों के उत्पादन एवं उपयोग में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। देश के लगभग सभी राज्यों में मुख्य एवं गौण बीजीय मसालों की खेती की जाती है। बीजीय मसालों को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य-धनिया, मैंथी, सौंफ, जीरा, गौण-अजवायन, सेलेरी, सुवा, कलौंजी आदि। गौण बीजीय मसालों के उत्पादन में राजस्थान और गुजरात सबसे अव्वल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं महाराष्ट्र आदि प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जो कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत पैदा करते हैं तथा इसी वजह से इन्हें 'बीजीय मसालों का कटोरा भी कहा जाता है।

देश में लगभग 9.7 लाख हैक्टर क्षेत्र पर बीजीय मसालों की खेती की जाती है जो की काफी बड़ी है और इससे प्रतिवर्ष कुल 5.6 लाख टन का उत्पादन होता है। बीजीय मसालों का विशेष महत्व इनमें पाए जाने वाले खुशबू एवं स्वाद के कारण होता है। विभिन्न बीजीय मसाला फसलों की उन्नत प्रजातियों का फसलवार वर्णन निम्न प्रकार है-

अजवाइन: एन.आर.सी.एस.एस.-ए.ए.-1. इस किस्म का विकास राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर द्वारा किया गया। इस किस्म को पक कर तैयार होने में लगभग 165 दिन का वक्त लगता है। और इसकी औसत उपज 14 क्विंटल/हैक्टर है। इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा 3.4 प्रतिशत पाई जाती है।

सुवा: एन.आर.सी.एस.एस.-ए.डी.-1. यह यूरदपीयन डील की किस्म है. यह किस्म सिंचित परिस्थितियों में अच्छी पैदावार देती है। इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा 3.5 प्रतिशत पाई जाती है।

एन.आर.सी.एस.एस.-ए.डी.- 2. यह भारतीय सुवा उन्नत की किस्म है। यह किस्म बारानी होती है तथा असिंचित और कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। इसमे वाष्पशीय तेल की मात्रा 3.2 प्रतिशत पाई जाती है।

सेलेरी: एन.आर.सी.एस.एस.-ए.सेल.- 1. यह राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर से हाल ही मयह किस्म विकसित होकर ए.आई.सी.आर.पी. के अन्तर्गत अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में खेती हेतु अनुमोदित की गई है। इस किस्म से 8-12 क्विंटल प्रति हैक्टर की उपज प्राप्त कर सकते है तथा बीजों में 2.4 प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है।

कलौंजी: एन.आर.सी.एस.एस.-ए.एन.- 1. यह किस्म राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर द्वारा विकसित की गई है और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जो लगभग 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। औसत उपज 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा वाष्पशील तेल की मात्रा 0.7 प्रतिशत है।

अजाद कलौंजी: यह किस्म कानपुर द्वारा विकसित की गई है जो लगभग 145 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उसकी औसत उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

पंतकृष्णा: यह किस्म पंतनगर से विकसित की गई है, जो 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

उन्नत प्रजातियां का चयन करके किसान भाई कम अवधि में पकने वाली फसल कीट एवं रोग के प्रति प्रतिरोधकता पायी जाने वाली एवं अधिक उपज देने वाली किस्मां का चयन करके अपनी उपज बढ़ा सकता है। जिससे अपनी एवं राष्ट्र को आय बढ़ा सकती है।

किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है कृषि यंत्र रोटावेटर

आधुनिकीकरण के इस दौर में किसानों के लिए कृषि यंत्र काफी सक्षम साबित हो रहे हैं। किसानों के कार्य को आसान बनाने में कृषि यंत्र ने एक सहायक भूमिका निभाई है। एक वक जहां किसान खेती के लिए अपने पूरे परिवार को उसमें सम्मिलीत करता था आज वो सारा काम यंत्रों की मदद से कम लोगों में भी कर सकता है। आज छोटे से लेकर हर बड़े कार्यों के लिए कृषि यंत्र किसानों के बीच उपलब्ध है। कृषि यंत्र ने एक तरफ जहां किसानों का कार्य आसान किया है वहीं इसके मदद से कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। कृषि यंत्र 'रोटावेटर' ऐसा कृषि यंत्र है जो किसानों को आमदनी बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। यह कृषि यंत्रों में काफी महत्वपूर्ण है। इस यन्त्र का उपयोग हरी खाद बनाने में भी किया जाता है। यह खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में उपयोगी है। इसका उपयोग गीली एवं सूखी दोनों तरह की भूमि को जोतने में किया जाता है। रोटावेटर का इस्तेमाल खासकर हल्की एवं मध्यम अवस्था वाली मिट्टी में चलने में पूर्ण सक्षम है। इसका प्रयोग 10 से 15 से.मी. गहराई तक की मिट्टी को मुलायम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोटावेटर एक बार की जुताई से ही खेत बुवाई के लिए तैयार किया जा सकता है और यंत्र को चलाने के बाद सीधे बुवाई किया जा सकता है। रोटावेटर को लगभग 40 से 50 अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टर की पी.टी.ओ. द्वारा शक्ति दी जाती है। यंत्र की फालें अंग्रेजी के अक्षर 'एल' आकार की होती है। यह एक के बाद एक विपरीत दिशा में रोटर शॉफ्ट पर लगी होती हैं, जो कि ट्रैक्टर के पी.टी.ओ. शॉफ्ट द्वारा लगभग 210 आर.पी.एम. पर चलाई जाती हैं। यह मशीन एक बार में ही मिट्टी को भुरभुरी तथा बुवाई योग्य बना देती है। इस यंत्र के पीछे मिट्टी तो समतल करने के लिए एक लेवलर भी लगा रहता है जिससे मिट्टी भुरभुरी एवं समतल हो जाती हैं।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।
विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के गुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

S.S.AGRO (INDIA)-MUM-
DIRECT IMPORT FOR YOUR FERTILIZER/CHEMICALS

- ZINK EDTA/COPPER
- EDTA/FF/EDTA
- 100% WATER SOLUBLE
- FERTILIZER (NPK)
- HUMIC ACID
- SEAWEED EXTRACT
- AMINO ACID
- POTASSIUM HUMATE
- FULVIC ACID
- EDDHA
- NATCA
- BRASSINOLIDE
- DAP
- SODA ASH
- SODIUM SULPHIDE
- AMONIUM CLORIDE
- SODIUM BICARBONATE
- CALCIUM CARBIDE
- PHOSPHORIC ACID
- TRI SODIUM PHOSPHATE
- CITRIC ACID
- STPP

ALL KIND OF INORGANIC
ORGANIC CHEMICALS
CONTACT NO. 022-6710-3722

महाराष्ट्र में कपास पर फिर पिंक बॉलवर्म

मुंबई। भारतीय कपास संघ द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस बार खरीफ सीजन में भी पिछले कुछ दिनों के दौरान पिंक बॉलवॉर्म द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाए जाने की खबरें मिली हैं। इस कीड़े की वजह से पिछले साल फसल को हुए नुकसान की पहचान अब तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जा सकी है ताकि किसानों को नुकसान की भरपाई की जा सके। पिंक बॉलवॉर्म ने पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को कपास फसल को नुकसान पहुंचाया है और तीसरी बार भी इस तरह का नुकसान हो सकता है। इस बार केंद्र सरकार ने इस कीड़े की वजह से हुए नुकसान के लिए महाराष्ट्र कपास किसानों के दावों को अभी तक मंजूरी नहीं दी है।

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के नेता राजू शेट्टी ने केंद्र से नुकसान से जुड़े किसानों के दावों को ठुकराने से पहले महाराष्ट्र सरकार के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण कराए जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के किसानों को पिंक बॉलवॉर्म के हमले की वजह से पिछले दो वर्षों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसी खबरें हैं कि केंद्रीय कृषि विभाग ने कीट के हमले से प्रभावित क्षेत्र को लेकर अनिश्चितता के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। राज्य सरकार के अधिकारियों

को आशंका है कि केंद्र वैशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फंड (एनडीआरएफ) के तहत अपनी वित्तीय सहायता में कटौती कर सकता है या किसानों के दावों को संदिग्ध पाए जाने की स्थिति में कोई रकम मुहैया नहीं करा सकता है। राजू शेट्टी ने कहा, 'किसानों को सहायता मुहैया कराने के संदर्भ में सरकारी दृष्टिकोण अनुकूल नहीं है। कीट के हमले की वजह से नुकसान पिछले दो वर्षों में काफी ज्यादा हुआ है। यहां तक कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी किसानों को मदद नहीं मिली है।'

सीएआई के अनुसार, महाराष्ट्र में कपास वर्ष 2016-17 (अक्टूबर से सितंबर) में कपास की बुआई 37 लाख हेक्टेयर में की गई थी जबकि उत्पादन 89 लाख गांठ था और 2017-18 में रकबा बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर हो गया जबकि फसल उत्पादन घटकर 82 लाख गांठ रह गया और 2018-19 में शुरुआती संकेतों से पता चला है कि रकबा घटकर 38 लाख हेक्टेयर रह जाएगा जबकि फसल उत्पादन 75 से 80 लाख गांठ के साथ काफी कम रह सकता है। सीएआई के अध्यक्ष अतुल गनात्रा का कहना है कि महाराष्ट्र में फसल उत्पादन घटकर पूरे देश में सबसे कम रह गया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत के स्तर पर औसत पैदावार प्रति हेक्टेयर तीन गांठ है जबकि महाराष्ट्र में 2017-18 में यह प्रति हेक्टेयर दो गांठ पर रहने का अनुमान है जो सबसे कम है। सीएआई के निदेशक मनीष डागा ने यह सर्वेक्षण किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस साल भी पिंक बॉलवॉर्म की समस्या पिछले कई दिनों में दिखनी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इसका प्रकोप बढ़ने का अनुमान है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति लायेगी सरकार : मोदी

नई दिल्ली (विसं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार जल्दी ही कृषि निर्यात नीति लाएगी। सरकार वर्ष-2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार द्वारा खेती और किसानों के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए फसल पर आने वाली कुल लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊंचे एमएसपी की पिछले कई साल से किसानों द्वारा मांग उठाई जा रही थी। हमने निर्णय किया है कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत का डेढ़ गुना दाम मिलना चाहिए और इसे लागू किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था तब इसको लेकर संदेह जताए गए लेकिन एमएसपी में वृद्धि जैसे निर्णय से सरकार लक्ष्य हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बदलते समय में

किसानों को भी वैश्विक बाजारों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इस संदर्भ में कृषि निर्यात नीति पर काम कर रही है। हालांकि उन्होंने नीति के बारे में ज्यादा ब्योरा नहीं दिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मार्च में कृषि निर्यात नीति का मसौदा पेश किया है जिसका मकसद कृषि निर्यात को दोगुना करना तथा भारतीय किसानों एवं कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करना है। मोदी ने कहा कि देश रिकॉर्ड खाद्यान का उत्पादन कर रहा है। हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है। उन्होंने कहा कि किसान सूक्ष्म, सिंचाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई को अपना रहे हैं। सरकार अटकी पड़ी 99 सिंचाई परियोजनाओं का पुनरूद्धार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'बीज से बाजार तक' के रुख के साथ हम कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव ला रहे हैं। आज हमारा पूरा जोर कृषि क्षेत्र में बदलाव और उसे आधुनिक रूप देने पर है। कुछ लोग किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर संदेह जता रहे हैं लेकिन सरकार का इरादा दृढ़ है।

उदित ओवरसीज प्रा.लि.

राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक अब मान्यता प्राप्त दरों व अनुदान पर उपलब्ध

फर्टिलाइजर

1. जिंक सल्फेट 21 प्रश.
2. जिंक सल्फेट 33 प्रश.
3. फेरस सल्फेट 19 प्रश.
4. कॉपर सल्फेट 24 प्रश.
5. मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 प्रश.

बायो फर्टिलाइजर

1. राइजोबियम पाउडर
2. एजेटोबेक्टर पाउडर
3. पी.एस.बी. पाउडर

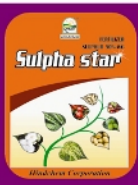

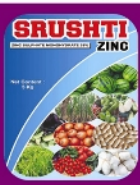

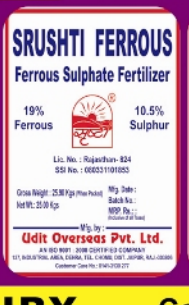

FERTILIZER

- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- FERROUS EDTA 12%
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

BIO FERTILIZERS

- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

WELCOME INQUIRY Contact : 7975653498 (Rajesh

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425